परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	शहरी गरीबों को स्वरोजगाार हेतु कार्यक्रमों को संचालित कर हितग्राहियों को कियान्वयन हेतु	362991	निम्नाकिंत घटक शहरी गरीबों के लिए कियान्वित होगें :- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व-स्वरोजगार कार्यक्रम 4. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी वेघरों के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक ण्वं अन्य व्यय 8. सूचना सम्प्रेषण मद	
2	स्मार्ट सिटी	राजधानी रायपुर का स्मार्ट सिटी के मापदण्ड अनुरूप विकसित करना।	3780000	स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रो फिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन सिटी प्रयास, जिसमें शह के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट सॉल्यूशन) लागू किया जाता है ।	
3	स्वच्छ भारत अभियान	यह केन्द्रीय योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 341310 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्यूनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है ।	1580000	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । भारत सरका से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 3413 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्यूनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है ।	
4	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लि	2341000		

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		क्रियान्वयन होंगे:- 1. झुग्गी बस्ती पुर्नविकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण		वर्ष 2015-2022 तक सभी पात्र परिवारों को 30 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल आकार के अधोसंरचनायुक्त पक्के आवास प्रदान करने के लिए केन्द्राय सहायता का प्रावधान है । प्रथम श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए 04 चरणों में क्रियान्वयन किया जाना है ।	
5	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए बर्षा जल नाले 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किग स्थल 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्को और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना ।	2310000	राज्य के 09 शहरों-रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकाप्ु को अमृत मिशन हेतु चयनित किया गया ।	
6	झुग्गी झोपड़ी पेयजल तथा शौचालय निर्माण	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना	94100	नगरीय निकायों में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था	
7	नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रसाधन	निकायों में सार्वजानिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षित तथा निजता और प्रतिष्ठा के अनुरूप सर्व सुलभ सार्वजानिक प्रसाधन		168 के नगरीय निकाय में महिला सार्वजानिक प्रसाध निर्माण कार्य हेतु ।	
8	वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय किया जाना है ।	100000	168 निकाओं में आवश्यकतानुसार वॉटर ए.टी.एम. क स्थापना	

परिणामी बजट वर्ष 2018–19

विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
9	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार पेयजल, प्रकाश सार्वजनिक शौचालय साफ सफाई एवं सामुदायिक भवन आदि के लिए अनुदान	720500	168 नगरीय निकायों के लिए निम्नाकिंत कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. ठोस अवशिष्ट सामग्री क्रय प्रबंधन	
10	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन	राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चालू होने से राज्य के 141 नगरीय निकाय के कुल बीपीएल जनसंख्या 9,74,166 जिसमें 2,35,387 गरीब परिवारों का आजीविका, कौशल उन्नयन तथा जमीनी स्तर के संस्थाओं के निर्माण गतिविधियों से वंचित हो जायेंगे जिसकी पूर्ति के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन नवीन योजना लागू किया जावेगा ।	400	राज्य के 141 नगरीय निकाय के कुल बीपीएल जनसंख्या 9,74,166 जिसमें 2,35,387 गरीब परिवारों का आजीविका तथा जमीनी स्तर के संस्थाओं के निर्माण गतिविधियों से वंचित हो जायेंगे जिसकी पूर्ति के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन नवीन योजना लागू किया जावेगा ।	
11	विशिष्ट प्रयोजनार्थ	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान निश्चित अनुपात में स्वीकृत किया जाता है ।	650000	नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हे तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना में नगर निग हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 4(प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है ।	
12	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना	1350	जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएगें।	dksb

परिणामी बजट वर्ष 2018–19

विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
13	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	5757050	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान राशि की मांग की गई है जिसमें अंतर्गत निम्नानकित कार्य प्रमुखत: से किया जाना है । 1. मास्टर प्लान/सी.डी.पी के मुख्य मार्ग 2. फ्लाई ओव्हर निर्माण 3. मल्टी लेवर पार्किग स्थल निर्माण 4. पशु वंध गृह निर्माण 5. नगरीय जल प्रदाय योजना 6. स्पोटर्स काम्पलेक्स 7. बिलासपुर/रायपुर में फ्लाई ओव्हर निर्माण 8. नगरीय निकायो में हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण 9. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कामकाजी महीला छात्रावास का निर्माण	